Online at: https://researchtrendsjournal.com ISSN No: 2584-282X

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 1; Issue 1; 2023; Page No. 324-328

Received: 18-09-2023
Accepted: 29-10-2023

किसानों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन और आंदोलन

[1]Visvas and [2]Dr. Sunil Kumar

[1]Research Scholar, Sunrise University, Alwar, Rajasthan, India
[2]Associate Professor, Sunrise University, Alwar, Rajasthan, India

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14555328

Corresponding Author: Visvas

सारांश

किसानों के अधिकारों पर इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए उठाए जाने वाले ठोस उपायों पर खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय को प्रस्तावों के लिए एक आम समझ को सुविधाजनक बनाने और एक अनुभवजन्य आधार विकसित करने के लिए किसान अधिकार परियोजना की स्थापना की गई है। यह पृष्ठभूमि अध्ययन इन अधिकारों पर दस्तावेज़ीकरण और साहित्य के एक व्यापक सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। इसे वार्ताकारों, चिकित्सकों और शोधकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में डिज़ाइन किया गया है जो किसानों के अधिकारों की अवधारणा और संभावनाओं को समझना चाहते हैं। दस्तावेज़ लंबी और जटिल वार्ता के परिणामों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और किसानों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करते हैं। खाद्य और कृषि के लिए फसल आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करने, सुधारने और उपलब्ध कराने में किसानों को उनके पिछले, वर्तमान और भविष्य के योगदान के लिए कैसे पुरस्कृत किया जाए, यह वार्ता में एक केंद्रीय विषय रहा है। इसमें किसानों को समर्थन और सहायता देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कोष लंबे समय से एजेंडे में है। चर्चाओं ने इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया है कि कैसे किसानों के अधिकार प्रजनकों के अधिकारों को संतुलित कर सकते हैं, ताकि एक न्यायसंगत प्रणाली सुनिश्चित हो सके जो किसानों को फसल आनुवंशिक संसाधनों तक निरंतर पहुँच और उनके मुफ़्त उपयोग की सुविधा प्रदान कर सके।

मुख्य शब्द: किसानों के अधिकार, पारंपरिक ज्ञान, लाभ साझा करना

प्रस्तावना

चरण सिंह (1902-87) को अक्सर 'भारत के किसानों के चैंपियन' के रूप में पहचाना जाता है। यह वर्णन एक सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में उनके लंबे करियर को संदर्भित करता है। उनके लिखित कार्य कम ही जाने जाते हैं। इसका उल्लेख शायद ही कभी किया जाता है, और जब किया जाता है, तो स्वर खारिज करने वाला होता है। यहाँ सबसे पहले यह तर्क दिया जाता है कि चरण सिंह वास्तव में एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, लेकिन उन्होंने पूरे किसानों के हितों का नहीं, बल्कि इसके अमीर और मध्यम वर्ग के हितों का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया। दूसरा, यह सुझाव दिया जाता है कि उनका प्रकाशित कार्य आम तौर पर स्वीकार किए जाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है; यह पूरी तरह से नव-लोकलुभावनवाद की व्यापक परंपरा में आता है; और यह कि वे असामान्य रूप से अमीर और मध्यम किसानों के एक सच्चे 'जैविक' बुद्धिजीवी थे। उनका राजनीतिक करियर और उनके विचार दोनों ही अब तक की तुलना में अधिक गंभीर ध्यान देने योग्य हैं; और इस तरह के ध्यान के लिए पर्याप्त वर्ग परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है।

1952 और 1968 के बीच, वे "कांग्रेस की राज्य राजनीति में तीन प्रमुख नेताओं में से एक थे।" वे विशेष रूप से उल्लेखनीय बन गए । उत्तर प्रदेश 950 के दशक से तत्कालीन मुख्यमंत्री के संरक्षण में भारत के किसी भी राज्य में सबसे क्रांतिकारी भूमि सुधार कानूनों का मसौदा तैयार करने और उन्हें पारित कराने के लिए गोविंद बल्लभ पंत; पहले जैसा संसदीय सचिव और फिर भूमि सुधारों के लिए जिम्मेदार राजस्व मंत्री के रूप में वह 1959 से राष्ट्रीय मंच पर दिखाई देने लगे, जब उन्होंने निर्विवाद नेता और प्रधानमंत्री का सार्वजनिक रूप से विरोध किया जवाहरलाल नेहरू का नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में समाजवादी और सामूहिक भूमि नीतियों पर चर्चा की। हालांकि गुटों में बंटी उत्तर प्रदेश कांग्रेस में उनकी स्थिति कमजोर हो गई थी, लेकिन यह वह समय था जब उत्तर भारत में जातियों के बीच के मध्यम किसान समुदाय उन्हें अपने

प्रवक्ता और बाद में अपने निर्विवाद नेता के रूप में देखने लगे। सिंह ने सरकारी खर्च में कटौती, भ्रष्ट अधिकारियों के लिए दंडात्मक *कारवाई* और "सरकारी कर्मचारियों की वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांगों से निपटने में सख्ती" की वकालत की। यह भी ध्यान देने योग्य है कि गुटों में बंटी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भीतर, अपनी स्पष्ट नीतियों और मूल्यों को व्यक्त करने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपने सहयोगियों से अलग खड़ा कर दिया। इस अवधि के बाद, चरण सिंह 1 अप्रैल 1967 को कांग्रेस से अलग हो गए, विपक्षी पार्टी में शामिल हो गए और यूपी के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। यह वह दौर था जब 1967 से 1971 तक भारत में गैर-कांग्रेसी सरकारें एक मजबूत ताकत थीं।

साहित्य की समीक्षा

डे, इंद्रनील और पोहित, संजीब (2020)। भारत में कृषि विरोध प्रदर्शनों में अमीर किसान हावी हैं। यह चरण सिंह के दिनों से हो रहा है। भारत में कृषि विरोध प्रदर्शनों में अमीर किसान हावी हैं। यह चरण सिंह के दिनों से हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े और मध्यम उद्योगों की तरह कृषि क्षेत्र को भी एक सुव्यवस्थित उद्योग प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।

प्रताप, भानु एवं लाइब्रेरियन, सहायक एवं सिंह, चौधरी. (2019).वर्तमान अध्ययन चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कृषि वैज्ञानिकों की सूचना आवश्यकताओं और सूचना प्राप्त करने के व्यवहार का विश्लेषण करता है। कृषि वैज्ञानिक विभिन्न पैटर्न में जानकारी चाहते हैं। डेटा एकत्र करने के लिए प्रश्नावली विधि का उपयोग किया गया था। विभिन्न विषयों को कवर करने वाले कृषि वैज्ञानिकों को कुल 200 प्रश्नावली वितरित की गईं और 147 भरी हुई प्रश्नावली वापस कर दी गईं, जिससे कुल प्रतिक्रिया दर 73.50% रही। यह पाया गया कि 60.54% उत्तरदाता CeRA डेटाबेस से पत्रिकाओं का उपयोग करने के लिए पुस्तकालय आते हैं। अधिकांश (51.70%) उत्तरदाता ने अपनी वांछित जानकारी के लिए प्रिंट के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध विभिन्न सूचना संसाधनों से लेखों की समीक्षा की। 70% से अधिक उत्तरदाताओं ने सूचना के चैनल के रूप में इंटरनेट को प्राथमिकता दी है। लगभग 44.21% उत्तरदाता पुस्तकालय द्वारा प्रदान की गई ई-जर्नल (CeRA जर्नल/डेटाबेस) सेवाओं की पर्याप्तता से संतुष्ट थे, जबकि 38.09% उत्तरदाता ई-थीसिस के उचित संग्रह से काफी संतुष्ट थे। निष्कर्ष यह निकला कि अधिकांश कृषि वैज्ञानिक सीसीएसएचएयू, हिसार के नेहरू पुस्तकालय द्वारा प्रदान की गई समग्र सुविधाओं और सेवाओं से संतुष्ट थे।

ककरालिया, एसके और सिंह, ईश्वर और दादरवाल, आरएस और सिंह, लव कुमार और जाट, डॉ और जाट, एचएस और जाट, एमएल. (2018).चावल (ओरिज़ा सातिवा एल.)-गेहूं (ट्रिटिकम एस्टिवम एल.) उत्पादन प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में प्रमुख योगदानकर्ता हैं, जो अनुपयुक्त प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों, इनपुट और प्रौद्योगिकियों के उपयोग के कारण समय के साथ अस्थिर हो गई और जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिमों से और बढ़ गई है। और यदि उत्पादन में हमेशा की तरह व्यवसाय दृष्टिकोण अनुमानित जलवायु परिवर्तन प्रभावों का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए, चावल और गेहूं उत्पादकता की स्थिरता के लिए विभिन्न संयोजनों में प्रमुख प्रौद्योगिकियों, प्रथाओं और सेवाओं की परत के प्रभावों का मूल्यांकन करने और सामान्य व्यवसाय (किसान अभ्यास) के साथ तुलना करने के लिए एक बहु-स्थान किसान की भागीदारी रणनीतिक शोध आयोजित किया गया था। हमारे वर्तमान अध्ययन में, छह परिदृश्य: किसान अभ्यास (एफपी); अनुकूली उपायों की कम तीव्रता के साथ बेहतर एफपी (आईएफपी); सीएसए की तुलना उच्च तीव्रता वाले अनुकूली उपायों (सीएसए-एच) से की गई। परिणामों से पता चला कि सीएसएपी (सीएसए-एल, सीएसए-एम और सीएसए-एच) में एफपी (रोपा हुआ चावल; टीपीआर) की तुलना में अधिक पौधे की ऊंचाई, प्रति वर्ग मीटर पुष्पगुच्छ और जैवभार संचयन लेकिन प्रति पुष्पगुच्छ कम दाने और 1000 दाने का वजन दर्ज किया गया। विभिन्न प्रबंधन परिदृश्यों में चावल की पैदावार पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। आईएफपी-एएम, सीएसए-एल, सीएसए-एम और सीएसए-एच के तहत प्रति पुष्पगुच्छ में खाली दाने एफपी की तुलना में 17, 18, 15 और 14% अधिक थे।

सिवाच, अनिल और परमार, सीमा (2018).सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएसएचएयू) आईसीएआर रैंकिंग 2016-17 के अनुसार भारत के शीर्ष दस कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है। 2001-2015 के दौरान इस विश्वविद्यालय में प्रकाशन प्रवृत्तियों का पता लगाने के लिए वर्तमान अध्ययन किया गया है। अध्ययन मुख्य रूप से वर्ष-वार शोध आउटपुट, प्रमुख विषय श्रेणियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रकाशन के लिए शीर्ष पत्रिकाओं, सबसे विपुल लेखकों, कीवर्ड, लेखकत्व पैटर्न, उद्धरण पैटर्न और सीसीएसएचएयू के अत्यधिक उद्धृत पेपर पर केंद्रित है। विश्वविद्यालय के 15 साल के प्रकाशन डेटा से संकेत मिलता है कि 2001-2015 तक कुल 2649 पेपर प्रकाशित हुए, जिन्हें 15282 उद्धरण मिले। विश्वविद्यालय के लगभग 47% शोध दस पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए और इसने अपने शोध प्रकाशन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संस्थानों के साथ सहयोग किया है।

कृषि शिक्षा और तकनीकी विकास

कृषि शिक्षा दुनिया भर में कृषि प्रणालियों की प्रतिस्पर्धात्मकता का एक मूलभूत हिस्सा है। इस प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए, कृषि शिक्षा को पाठ्यक्रम विकास और वितरण में शैक्षिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना चाहिए। इसलिए, शिक्षण और सीखने में संवादात्मकता लाने और बेहतर परिणाम देने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग ने पिछले कुछ वर्षों में इस विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों में बहुत अधिक शोध रुचि आकर्षित की है। इसके अलावा, उपलब्ध शैक्षिक प्रौद्योगिकियों में वृद्धि और COVID-19 महामारी के कारण उनके उपयोग में हाल ही में हुई वृद्धि ने उन प्रभावों को उजागर किया है जो शैक्षिक प्रौद्योगिकियां विकट परिस्थितियों में डाल सकती हैं।

इस स्कोपिंग समीक्षा ने कृषि शिक्षा कार्यक्रमों पर शैक्षिक प्रौद्योगिकियों के प्रभाव की जांच की। जेबीआई स्कोपिंग समीक्षा रूपरेखा के बाद, हमारे अध्ययन ने शोध निष्कर्षों को सारांशित करने और संप्रेषित करने, साहित्य के मौजूदा निकाय में शोध अंतराल खोजने और शोध गतिविधि के दायरे और चरित्र का आकलन करने का प्रयास किया। जबकि शोधकर्ता अभी भी कृषि शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकियों की विशिष्ट भूमिकाओं पर बहस करते हैं, कृषि शिक्षण और सीखने में शैक्षिक प्रौद्योगिकियों के योगदान का आकलन करना आवश्यक है। शैक्षिक प्रौद्योगिकियां एक आकस्मिक योजना से अधिक हैं, और सर्वोत्तम परिणामों के लिए उपयुक्त शिक्षण वातावरण में सबसे प्रभावी शैक्षिक प्रौद्योगिकियों को पूरी तरह से समझना, विकसित और तैनात करना महत्वपूर्ण है। कृषि शिक्षकों ने इन-सर्विस शिक्षा, व्यक्तिगत और समूह निर्देशात्मक उद्देश्यों और प्रशासनिक उद्देश्यों के पूरक जैसे क्षेत्रों में शैक्षिक प्रौद्योगिकियों को लागू किया है, और पाया है कि ये एकीकरण छात्रों की रुचि और प्रतिधारण को बढ़ाते हैं और

छात्रों की आलोचनात्मक सोच को बढ़ाते हैं। हालाँकि, शोध ने अभी तक मौजूदा शोध निष्कर्षों को सारांशित नहीं किया है और कृषि शिक्षा में भविष्य के शोध और कारवाई के लिए संभावित प्राथमिकताओं को उजागर नहीं किया है।

गठबंधन की राजनीति

बहुसांस्कृतिक समाजों में लोकतांत्रिक राजनीति अनिवार्य रूप से गठबंधन का एक अभ्यास है। समकालीन दुनिया में, संसदीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकार आदर्श बन गई है। दुनिया के कई देशों ने गठबंधन सरकारों का प्रयोग किया है जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इजरायल, आयरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत आदि। भारत में केंद्र और कुछ राज्यों में गठबंधन सरकारें एक नियमित विशेषता बन गई हैं। भारत ने 25 अक्टूबर 1946 को अपनी पहली गठबंधन सरकार देखी, जब जवाहरलाल नेहरू ने भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की छाया में नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) - मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार बनाई, जबकि भारत का शाही विभाजन सिर पर मंडरा रहा था। इस गठबंधन सरकार ने मात्र नौ महीने की अवधि तक काम किया। स्वतंत्रता के बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसे भारत में लोगों की लोकप्रियता, सम्मान और व्यापक समर्थन प्राप्त था। 1947 से 1967 तक, कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी बनी रही, और केंद्र के साथ-साथ राज्यों में भी इसका एकाधिकार था । 1967 के आम चुनावों के बाद, भारत ने अपनी राजनीति में एक नए युग का अनुभव किया, जिसने सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को दर्शाया, जो पहले कांग्रेस प्रणाली में केंद्रित थी, जो आधे से अधिक भारतीय राज्यों में विभिन्न दलों और पार्टी गठबंधनों को दी गई थी। हालाँकि कांग्रेस 1977 के चुनावों तक संघ स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी बनी रही, जब इसे जनता सरकार के रूप में जाने जाने वाले गैर-कांग्रेसी गठबंधन द्वारा सत्ता से बाहर कर दिया गया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, इसकी गिरावट और गैर-कांग्रेसी गठबंधन सरकारों के उद्भव का पता लगाना है।
ग्रामीण विकास, ग्रामीण परिवेश में सुधार की प्रक्रिया है।जीवन स्तरऔर आर्थिक हाल चाल_में रहने वाले लोगों की ग्रामीण इलाकों, प्रायः अपेक्षाकृत पृथक और कम आबादी वाले क्षेत्र। प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या देखने को मिलती है, ग्रामीण गरीबी_आर्थिक गतिविधियों तक पहुंच की कमी और शिक्षा जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे में निवेश की कमी के कारण शहरी या उपनगरीय आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में गरीबी अधिक है।

किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले संघों और आंदोलनों

देश के ग्रामीण और शहरी आर्थिक अंतर्विरोध के खिलाफ चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर धुर किसान राजनीति शुरु की गाजियाबाद जिले के नूरपुर गांव में स्वतंत्र भारत में एक महत्वपूर्ण किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने किसानों के मुद्दों और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उनके लिए खड़े रहे। किसान नेता छोटू राम की विरासत को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने ग्रामीण जनता के बीच किसानों के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 23 दिसंबर, 1978 को अपने 76वें जन्मदिन पर किसान ट्रस्ट की स्थापना की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक किसान परिवार में जन्मे, वे राज्य के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे और फिर केंद्रीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री, उप प्रधान मंत्री और अंततः प्रधानमंत्री बने। किसान यह दिवस हमारे देश के लिए उनके दो सबसे महत्वपूर्ण योगदानों को याद करने का एक अच्छा दिन है। सबसे पहले, जवाहरलाल नेहरू और पीसी महालनोबिस - योजना आयोग के पहले प्रमुख - के विरोध में उन्होंने भारत के लिए विकास का एक वैकल्पिक मॉडल पेश करने का प्रयास किया जो गांधी से प्रेरित था और उनके अपने किसान मूल का प्रतिबिंब था। दूसरा, उन्होंने 1960 और 1970 के दशक के दौरान किसानों के मुद्दों को भारत की चुनावी राजनीति में - राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर - शामिल किया।
चरण सिंह नेहरू के संयुक्त और सहकारी खेती के प्रस्ताव के भी कट्टर आलोचक थे। 1959 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उन्होंने सहकारी खेती के पक्ष में प्रस्ताव के खिलाफ एक घंटे लंबा भाषण दिया। हालांकि उनके भाषण की अखबारों और कांग्रेस नेताओं ने सराहना की, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व में कई लोगों ने इसकी निंदा की। संयुक्त खेती की एक सशक्त आलोचना पेश करते हुए उन्होंने उसी वर्ष एक किताब लिखी, जिसका नाम था, ज्वाइंट फार्मिंग एक्स-रेड: द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। उन्होंने संयुक्त खेती की आलोचना की क्योंकि उनका मानना था कि व्यक्तिगत भूमि जोत का एकीकरण कभी सफल नहीं हो सकता क्योंकि किसान अपनी जमीन से जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी सफलता के लिए कृषि के मशीनीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने भूमि पर उन लोगों का स्वामित्व रखने का तर्क दिया जो इसे जोतते हैं। उनके लिए किसान स्वामित्व गांधी के ग्रामीण लोकतंत्र और आर्थिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण के विचार के अनुरूप था।
चरण सिंह 1960 और 1970 के दशक में पहले उत्तर प्रदेश और फिर राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की राजनीति के प्रतिनिधि बन गए। उन्होंने उत्तर भारत में किसानों के राजनीतिकरण और संसदीय राजनीति में उनकी स्वतंत्र आवाज़ के रूप में पहचान बनाने का नेतृत्व किया, जिस पर अलग से ध्यान देने की ज़रूरत है। 1967 में कांग्रेस से अलग होने के बाद, उन्होंने उत्तर प्रदेश में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनाई और मुख्यमंत्री का पद संभाला। उन्होंने 1967 में अन्य लोगों के साथ मिलकर भारतीय किसान दल (बीकेडी) का गठन किया। पार्टी का ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा-खासा आधार था, जो किसानों के मुद्दों के लिए प्रतिबद्ध थी और आज़ादी के बाद की राजनीति में पहली बार किसान नेताओं के नेतृत्व में इसका नेतृत्व किया गया था।

जमींदारी उन्मूलन

सरकार और जमींदारों के बीच भूमि के एकाधिकार ने कुछ लोगों के हित में बहुत से लोगों के औपनिवेशिक शोषण को कायम रखा था। जमींदार को इन जमीनों से किराया वसूलने के लिए मध्यस्थ होने के बदले में सरकार द्वारा भूमि का स्वामित्व दिया गया था, और अपनी सेवाओं के लिए उसने अपनी जमीन पर खेती करने वाले किरायेदारों से जितना संभव हो सके उतना किराया वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखा था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने राजस्व के लिए जमींदार को निचोड़ा, जमींदार किरायेदार था जिसके पास सरकार और उसके कानून के दमन की शक्तिशाली मशीनरी के खिलाफ कोई सहारा नहीं था। उपनिवेशवादी और जमींदार के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग के परिणामस्वरूप इस गठजोड़ के हाथों में शक्ति और धन का अत्यधिक संकेन्द्रण हुआ। उपनिवेशवाद के तहत भारतीय कृषि किसानों का बहुत शोषण करती थी, इससे उत्पन्न राज्य राजस्व का बड़ा हिस्सा जमींदार बिचौलियों द्वारा हड़प लिया जाता था। बीसवीं सदी की

शुरुआत तक, भूमि राजस्व औपनिवेशिक राज्य राजस्व का आधा हिस्सा था, जिससे यह इन बिचौलियों पर निर्भर हो गया। इस प्रकार जमींदारी प्रथा फली-फूली और 1947 में स्वतंत्रता मिलने पर कुल कृषि योग्य भूमि का 60% से अधिक हिस्सा कुछ ही जमींदारों के पास था। तुलनात्मक रूप से, 60% से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास या तो कोई भूमि नहीं थी या उनके पास एक हेक्टेयर (2.5 एकड़) या उससे कम की गैर-आर्थिक जोत थी, उनके सामूहिक कब्जे में कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 8% था।

भारतीय हस्तशिल्प और उद्योग के औपनिवेशिक विनाश के कारण रोजगार प्रदान करने के लिए कृषि पर लगातार बढ़ते दबाव के कारण ये स्थितियाँ और भी गंभीर हो गईं, जिससे रैक किराए और किरायेदारी के लिए आदर्श स्थितियाँ पैदा हुईं। अनुपस्थित ज़मींदार और उप-सामंती प्रथाएँ3 बहुत ज़्यादा थीं, जबकि किरायेदारों पर लगाया जाने वाला किराया नियमित रूप से फ़सल के 50% से ज़्यादा था, कुछ क्षेत्रों में तो यह 85% तक भी पहुँच गया। इसके अलावा, ज़मींदार नकद, वस्तु या मज़दूरी (बेगार) के रूप में कई तरह की वसूली करते थे, जिससे किसान पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता था। इस शोषण का एक ख़ास तौर पर घिनौना रूप साहूकारों के एक वर्ग के रूप में विकसित हुआ, जो ज़मींदार की माँगों को पूरा करने के लिए किसानों को बहुत ज़्यादा दरों पर पूँजी उधार देते थे, जिससे ऋणग्रस्तता का चक्र चलता रहता था।

रूसी विकल्प

समस्या को स्पष्ट करने से आगे बढ़ते हुए, सिंह यूएसएसआर के मॉडल पर कृषि के सामूहिकीकरण के विकल्प का विश्लेषण करते हैं, जो "भूमि के निजी स्वामित्व और उसके राष्ट्रीय अधिग्रहण के पूर्ण उन्मूलन" पर आधारित है। यह विकल्प 2020 ई. में हमारे कानों को अजीब लग सकता है, जब 1990 के बाद से सभी रूपों में साम्यवाद को दफना दिया गया है, लेकिन 1940 के दशक में सामूहिकीकरण कई वैचारिक बुद्धिजीवियों के बीच एक स्वीकृत सिद्धांत था। सिंह भारत की स्वतंत्रता के समय रूस में प्रचलित परिस्थितियों और सामूहिक खेतों के विकास से शुरू करते हैं।

रूस में किसान अठारहवीं सदी तक दासता की स्थिति में थे, जो गुलामी की सीमा तक थी। शाही फरमान के द्वारा अपने जमींदारों से कानूनी रूप से बंधे हुए, उन्हें परिवारों में या अकेले खरीदा या बेचा जा सकता था, और उन्हें भूमि के अलावा संपत्ति के स्रोत के रूप में देखा जाता था। कराधान के उद्देश्यों के लिए उन्हें "कम्यून" में गठित किया गया था, जो सामूहिक रूप से अपनी भूमि से होने वाले राजस्व के लिए जिम्मेदार थे, और व्यक्ति इसमें अपने हिस्से के लिए जिम्मेदार थे।

"सामुदायिक व्यवस्था में समुदाय की कृषि गतिविधियों पर सामुदायिक नियंत्रण अनिवार्य रूप से शामिल था, इसलिए न केवल बुवाई और कटाई का समय, घास-फूस बनाना और इसी तरह के काम पूरे समुदाय के निर्णय पर निर्भर थे, बल्कि कौन सी फसल बोई जाए, किस क्षेत्र को खाली छोड़ा जाए, आदि भी इसी तरह तय किए जाते थे।" इस व्यवस्था में सुधार आंशिक रूप से 1861 के मुक्ति अधिनियम में हुआ, जिसने किसानों को बंधुआ स्थिति से मुक्त किया और उन्हें राज्य के प्रति कुछ देनदारियों के बदले में अपनी संबंधित भूमि के मालिक होने का विकल्प प्रदान किया। 1906 में स्टोलिपिन25 के तहत निर्णायक सुधार आए, जिसने किसानों को समुदाय से अलग होने का अधिकार दिया, जिस पर उन्हें जमीन का एक समेकित टुकड़ा दिया गया, जिस पर वे अपनी इच्छानुसार खेती कर सकते थे या बेच सकते थे। 1917 तक इन सुधारों ने रूस में पहली बार कुलक नामक समृद्ध ग्रामीण किसानों का एक वर्ग बनाया, जो बिक्री योग्य अधिशेष पैदा कर रहे थे।

सोवियत रूस

सिंह ने 1930 के दशक में रूसी कोलहोज (सामूहिक खेत) और सोवहोज (राज्य-खेत) के मौजूदा मॉडल का व्यापक सर्वेक्षण किया है। उन्होंने 1935 में सरकार द्वारा अपनाए गए एक आदर्श 'आर्टेल' या कोलहोज के गठन की रूपरेखा तैयार की, नीति में संशोधन के बाद जिसने किसानों को राज्य के आदेश से परे अधिशेष को अपनी इच्छानुसार किसी भी तरह से निपटाने की अनुमति दी, जिसमें इसे अनियंत्रित बाजार मूल्यों पर बेचना भी शामिल था।

सिंह ने आर्टेल में उद्देश्यों और लक्ष्यों, उत्पादन के साधनों, भूमि, संचालन और प्रशासन, सदस्यता की शर्तों और संगठन, भुगतान और श्रम के अनुशासन का कुछ विस्तार से सारांश दिया है। उनके उद्देश्यों में "कुलकों का विनाश" शामिल है और सामूहिकीकरण को "किसानों के लिए एकमात्र सही मार्ग" के रूप में स्वीकार किया गया है। राज्य द्वारा रखे गए *सम्मेलन* के पक्ष में व्यक्तिगत भूमि की सभी सीमाओं को समाप्त कर दिया जाना था, लेकिन आर्टेल को इसके उपयोग के लिए स्थायी रूप से हस्तांतरित कर दिया जाना था। भूमि को खरीदा, बेचा या पट्टे पर नहीं दिया जा सकता था। इसके अलावा, अगर कोई छोड़ना चाहता है, तो उसे कोई जमीन नहीं दी जानी थी क्योंकि जमीन केवल राज्य द्वारा दी जा सकती थी। "सभी काम करने वाले मवेशी, कृषि उपकरण (हल, ड्रिल, हैरो, आदि), बीज भंडार, सामूहिक पशुधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा, आर्टेल के काम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कृषि भवन और खेत के उत्पादों को तैयार करने के लिए सभी उद्यम" को साझा रखा गया, जबकि व्यक्तिगत घर, निजी पशुधन और उसके आवास और बुनियादी कृषि उपकरण आदि व्यक्तियों द्वारा बनाए रखे गए।

18 वर्ष से अधिक आयु के दोनों लिंगों के कार्यकर्ता सदस्यता के लिए पात्र थे, सिवाय कुलकों और "नागरिक अधिकारों से वंचित सभी व्यक्तियों" के, कुछ अपवादों के साथ। आर्टेल को कृषि उत्पादन के लिए सरकार की योजना के अनुरूप एक योजना का पालन करना था, जिसमें फसल की खेती और पशुधन की देखभाल शामिल थी। इसकी पहली प्राथमिकता राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य पर राज्य को अपना अनिवार्य हिस्सा सौंपना था, जिसके बाद प्रत्येक सदस्य की मजदूरी की गणना जनरल असेंबली में सहमत नियमों के अनुसार की जाती थी। मजदूरी श्रम के हिस्से और श्रम की विशेषज्ञता के अनुसार भिन्न होती थी, और जनरल असेंबली ने उन सदस्यों को दंडित करने या निष्कासित करने का अधिकार सुरक्षित रखा जो नियमों का पालन करने में विफल रहे, जो "समुदाय के प्रति राजद्रोह और लोगों के दुश्मनों का समर्थन" के समान था।अपराधियों को राज्य के अनिवार्य नियमों के अनुसार मुकदमा चलाने के लिए अधिकारियों को सौंपा जा सकता था। इन सभी एकीकरणों का उद्देश्य ट्रैक्टर जैसी बड़ी मशीनरी की तैनाती करना था, जिनके मशीन-ट्रैक्टर स्टेशन कोलहोज के संगठन के केंद्र में थे।

निष्कर्ष

भारतीय अर्थशास्त्री जी. पार्थसारथी ने 1978 में स्पष्ट व्यंग्य के साथ 'हमारे वक्तव्य-विद्वान, चरण सिंह' का उल्लेख किया । पार्थसारथी का यह कहना सही था कि चरण सिंह न तो वक्तव्यकर्ता थे और न ही विद्वान, यदि राजनेता का अर्थ है सरकार चलाने में कुशल

व्यक्ति, जो सरकार के प्रति विवेकपूर्ण और संकीर्ण पक्षपात के बिना काम करता है; और विद्वान का अर्थ है अकादमिक विशेषज्ञ, जिसका दृष्टिकोण समस्याओं की एक संकीर्ण सीमा के प्रति ईमानदार और आलोचनात्मक है। चरण सिंह इससे अलग थे, और उनका महत्व भी कम नहीं था। वे एक राजनीतिज्ञ-बुद्धिजीवी थे और, जैसा कि मैंने तर्क दिया है, एक उल्लेखनीय रूप से प्रभावी राजनीतिज्ञ और सबसे असामान्य बौद्धिक व्यक्ति थे।

मैंने सुझाव दिया है कि चरण सिंह एक आदर्श नव-लोकलुभावनवादी थे। जिन परिस्थितियों में नव-लोकलुभावनवाद पनपने की संभावना है, मैंने संकेत दिया है, वे पूंजीवाद के शुरुआती चरणों की हैं, इससे पहले कि यह अपने सामने सब कुछ बहा ले जाए और इससे पहले कि पूंजीवादी संबंध ग्रामीण इलाकों में पूरी तरह से हावी हो जाएं । मार्क्स ने पूंजी के जर्मन संस्करण की अपनी प्रस्तावना में ऐसी परिस्थितियों का भावपूर्ण वर्णन किया है। मार्क्स ने ठीक वही परिस्थितियाँ पकड़ी हैं जिनका हम यहाँ सामना कर रहे हैं । वह जर्मनी के बारे में कहते हैं: हम, महाद्वीपीय पश्चिमी यूरोप के बाकी हिस्सों की तरह, न केवल पूंजीवादी उत्पादन के विकास से पीड़ित हैं, बल्कि उस विकास की अपूर्णता से भी पीड़ित हैं। आधुनिक बुराइयों के साथ-साथ विरासत में मिली बुराइयों की एक पूरी श्रृंखला हमें परेशान करती है, जो पुराने उत्पादन के तरीकों के निष्क्रिय अस्तित्व से उत्पन्न होती है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक कालभ्रम की अपरिहार्य श्रृंखला होती है। हम न केवल जीवितों से बल्कि मृतकों से भी पीड़ित हैं।

जिस तरह के नव-लोकलुभावनवाद पर हम विचार कर रहे हैं, वह ठीक ऐसी ही स्थिति का जवाब है और जब तक यह स्थिति बनी रहेगी, तब तक यह अपनी ताकत बनाए रखेगा: 'संक्रमण' की स्थिति या पूंजीवाद का अधूरा विकास'। अगर हमें नव-लोकलुभावनवाद की मूल प्रकृति को व्यक्त करने के लिए एक शक्तिशाली रूपक चाहिए, तो वह निश्चित रूप से मार्क्स द्वारा दिया गया रूपक है: लेकिन नव-लोकलुभावनवाद जीवित और मृत दोनों से अपना पोषण प्राप्त करने के लिए कम शक्तिशाली नहीं है। यह तथ्य कि पूंजीवाद का विरोध किया जाता है और उस पर हमला किया जाता है, और नव-लोकलुभावनवाद के एक मजबूत संस्करण का समर्थन किया जाता है, चरण सिंह की विशेष रुचि है। यह खास विचारधारा एक ऐसे वर्ग की है जो अभी पूंजीवादी नहीं बना है, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया में है। यह एक तरफ तो उन भौतिक वास्तविकताओं को छिपाने का काम करता है, जिनसे चरण सिंह ने संबंधित बातें की हैं, और दूसरी तरफ अधूरे परिवर्तन के अंतर्निहित विरोधाभासों को व्यक्त करता है।

संदर्भ

1. सिवाच, अनिल, परमार, सीमा। सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार का शोध योगदान: एक ग्रंथसूची विश्लेषण। डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 2018;38:335-42. doi: 10.14429/djlit.38.5.13188।
2. डे, इंद्रनील, पोहित, संजीब। भारत में कृषि विरोध प्रदर्शनों में अमीर किसानों का दबदबा है: यह चरण सिंह के दिनों से हो रहा है। 2020.
3. प्रताप, भानु, लाइब्रेरियन, सहायक, सिंह, चौधरी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, भारत के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सूचना प्राप्ति के दृष्टिकोण। 2019;3:1-13.
4. ककरालिया, एस.के., सिंह, ईश्वर, दादरवाल, आर.एस., सिंह, लव कुमार, जाट, डॉ., जाट, एच.एस., जाट, एम.एल. उत्तर-पश्चिमी भारत-गंगा के मैदानों में चावल (ओरिज़ा सातिवा)-गेहूँ (ट्रिटिकम एस्टिवम) प्रणाली की वृद्धि और फसल पैदावार पर जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों का प्रभाव। भारतीय कृषि विज्ञान पत्रिका। 2018;88:1543-1551. doi: 10.56093/ijas.v88i10.84221.
5. सिवाच, अनिल, परमार, सीमा। सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार का शोध योगदान: एक ग्रंथसूची विश्लेषण। डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 2018;38:335-42. doi: 10.14429/djlit.38.5.13188.
6. ढांडा, पी. चरण सिंह के विचार विकास का एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक। 2019;54:35-42.
7. कुमार, राजेश, चहल, प्रदीप, घनघस, भारत, यादव, कृष्ण। कृषि छात्रों की आवासीय पृष्ठभूमि और शिक्षा में प्रदर्शन का अध्ययन करना। 2017।
8. गुलाटी, सुशील। बायोडाटा सुशील गुलाटी (sgbhuna@hau.ac.in; sgbhuna108@gmail.com)। (DST-INSPIRE वरिष्ठ अनुसंधान फेलो; पुरस्कार संख्या: IF160723) रसायन विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार। 2020. doi: 10.13140/RG.2.2.17972.88969.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.